सचिव, सैंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स और अन्य

बनाम

के. एस. महालिंगम

23 अप्रैल,1986

[ए. पी. सेन और मुरारी मोहन दत्त, न्यायाधिपतिगण]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 311(2) और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965, नियम 15(4) - सजा - का अधिरोण - कारण बताने को दूसरा अवसर - क्या आवश्यक है।

प्रतिवादी, एक सरकारी कर्मचारी को एक आरोप-पत्र सौंपा गया था, जिसमें आरोपों के दो अनुच्छेद शामिल थे, जिसमें ईमानदारी की कमी और कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी और एक सरकारी कर्मचारी के अशोभनीय आचरण से जुड़े कदाचार का आरोप लगाया गया था। अपने बचाव में प्रतिवादी ने आरोपों से इनकार किया। जांच अधिकारी ने माना कि आरोप की दोनों धाराएं स्थापित हो गईं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और अपने आदेश दिनांक 15 मई, 1980 द्वारा प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध, प्रतिवादी ने अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकारी ने 8 जुलाई 1981 के अपने आदेश द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निष्कर्ष

को बरकरार रखा। हालाँकि, इसने बर्खास्तगी के दंड को सेवा से प्रतिवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया।

प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। एकल न्यायाधीश ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया, यह कहते हुए कि आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था और चूंकि प्रतिवादी को सजा देने से पहले उसके खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था, बर्खास्तगी का आदेश दूषित था।

विभाग द्वारा की गई अपील में, खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की कि प्रतिवादी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उस पर लगाए गए दंड के खिलाफ कारण बताने के अवसर से वंचित किया गया था,एकल न्यायाधीश के आदेश को संशोधित किया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को निर्देश दिया कि प्रस्तावित सजा के खिलाफ कारण बताने के लिए नया नोटिस देने के चरण से प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को आगे बढ़ाएगा।

विभाग द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

(1) एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों का यह मानना उचित नहीं था कि बर्खास्तगी का आदेश दोषपूर्ण था क्योंकि प्रतिवादी को बर्खास्तगी

की सजा लागू करने से पहले उसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का दूसरा अवसर नहीं दिया गया था। [747 एफ-जी]

(2) खंडपीठ के फैसले को रद्द कर दिया गया है। चूंकि खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया, इसलिए पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद गुण-दोष के आधार पर अपील के निपटान के लिए मामले को खंडपीठ के पास भेज दिया जाता है। [747 एच; 748 ए-बी]

(3) संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 ने संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) से प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने के उचित अवसर की आवश्यकता को हटा दिया है और, इसके अलावा, इसे स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है खंड (2) का पहला परंतुक कि "ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा"। संशोधन के बाद, खंड (2) की आवश्यकता एक जांच आयोजित करके पूरी की जाएगी जिसमें सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। [746 ई-ई]

मौजूदा मामले में, प्रतिवादी को ऐसा अवसर दिया गया है। निर्विवाद रूप से बर्खास्तगी का आदेश पारित होने के बाद, प्रतिवादी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की गई, जिससे वह बर्खास्तगी के

आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने में सक्षम हो गया। [746 ई-एफ]

(4) संविधान के अनुच्छेद 311(2) के संशोधन के मद्देनजर, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 15(4) में संशोधन किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया कि सरकारी कर्मचारी को लगाए जाने वाले जुर्माने पर अभ्यावेदन का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। इसलिए, प्रतिवादी संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील), नियम, 1965 के नियम 15(4) के तहत सजा के खिलाफ कारण बताने के लिए दूसरे अवसर का दावा नहीं कर सकता है। [746 जी; 747 डी-ई]

भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेल, [1985] 3 एस.सी.सी. 389, पर भरोसा किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1279/1986

मद्रास उच्च न्यायालय, डब्ल्यू.ए.संख्या 809/1985 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30 सितंबर,1985 से।

आनंद प्रकाश,सी.वी. सुब्बा राव, आर.डी. अग्रवाल और टी.वी.एस.एन. अपीलकर्ताओं के लिए।

के.एस. महालिंगम, व्यक्तिगत रूप से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एम. एम. दत्त, जे. द्वारा पारित किया गया :-

अपीलकर्ताओं द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई प्रतिवादी को नोटिस देने पर की गई, जो व्यक्तिगत रूप से हमारे सामने उपस्थित हुआ। चूंकि विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई में दोनों पक्षों द्वारा दलीलें दी गई हैं, हम ऐसी अनुमति देने के बाद अपील का निपटान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

इस अपील में एकमात्र प्रश्न शामिल है, क्या प्रतिवादी को सजा देने से पहले उसके खिलाफ दूसरा कारण बताओ नोटिस देना और उसे जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करना आवश्यक है।संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम,1976 द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) में संशोधन और केंद्रीय सिविल-सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 15(4) में परिणामी परिवर्तन लाया गया। वास्तव में, प्रतिवादी को दी गई विशेष अनुमति याचिका की सूचना केवल उक्त प्रश्न तक ही सीमित थी।

प्रतिवादी, के.एस. महालिंगम, मद्रास कस्टम्स हाउस के परीक्षक थे। जब वह उस क्षमता में कार्य कर रहा था, उसे एक आरोप पत्र सौंपा गया था जिसमें आरोप के दो अनुच्छेद शामिल थे जिसमें कदाचार का आरोप लगाया गया था जिसमें सत्यनिष्ठा की कमी और कर्तव्य के प्रति समर्पण

की कमी और एक सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय आचरण शामिल था। प्रतिवादी ने अन्य बातों के साथ-साथ आरोपों से इनकार करते हुए अपना बचाव प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी ने माना कि आरोप की दोनों धाराएं स्थापित हो गईं। अनुशासनात्मक प्राधिकारी, अर्थात्, सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट की जांच की और अपने आदेश दिनांक -15 मई, 1980 द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए दोनों आरोप साबित हुए थे।उक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, सीमा शुल्क कलेक्टर ने अपने उक्त आदेश द्वारा प्रतिवादी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी ने इसके खिलाफ मुख्य सतर्कता अधिकारी, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समक्ष अपील दायर की। अपीलीय प्राधिकरण ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विस्तार से विचार किया और 8 जुलाई, 1981 के अपने आदेश द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकरण के निष्कर्ष को बरकरार रखा कि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप साबित हुए थे। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकारी ने बर्खास्तगी के दंड को सेवा से प्रतिवादी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया।

प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। विद्वान न्यायाधीश, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों की समीक्षा के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सरकारी कर्मचारी के प्रति सत्यनिष्ठा की कमी या कर्तव्य के प्रति समर्पण की कमी या

अशोभनीय आचरण का कोई सबूत नहीं था, जैसा कि प्रतिवादी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में बताया गया है। इसके अलावा, विद्वान न्यायाधीश ने यह विचार किया कि चूंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सजा दिए जाने से पहले प्रतिवादी को सजा के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था और चूंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट की कोई प्रति उन्हें नहीं दी गई थी, इसलिए बर्खास्तगी का आदेश दूषित था। तदनुसार, विद्वान न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 7 सितंबर, 1985 द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादी को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। खंडपीठ ने 13 सितंबर, 1985 को अपने फैसले में विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमति व्यक्त की कि प्रतिवादी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उस पर लगाए गए दंड के खिलाफ बोलने के अवसर से वंचित किया गया था। मामले के उस दृष्टिकोण में, खंडपीठ ने विद्वान न्यायाधीश के निष्कर्षों पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया। खंडपीठ ने प्रतिवादी को सेवा में बहाल करने के निर्देश को रद्द करके और अनुशासनात्मक प्राधिकारी को उसके द्वारा प्रस्तावित दण्ड के लिये कारण बताने के लिए नया नोटिस देने के चरण से प्रतिवादी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देकर विद्वान

एकल न्यायाधीश के आदेश को संशोधित किया। इसलिए अपीलकर्ताओं द्वारा यह अपील।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि खंडपीठ और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी यह विचार किया कि बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया गया था क्योंकि अनुशासनात्मक प्राधिकारी प्रतिवादी को कारण बताने का अवसर देने में विफल रहा। बर्खास्तगी की सज़ा के ख़िलाफ़, इससे पहले कि उस पर यह सज़ा लागू की गई थी। उच्च न्यायालय की खंडपीठ और विद्वान एकल न्यायाधीश दोनों ने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है कि संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 ने संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) से उचित अवसर की आवश्यकता को हटा दिया है। प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का और, इसके अलावा, खंड (2) के पहले प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि "ऐसे व्यक्ति को प्रस्तावित दंड पर प्रतिनिधित्व करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा"। संशोधन के बाद, खंड (2) ए की आवश्यकता को एक जांच आयोजित करके पूरा किया जाएगा जिसमें सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया जाएगा और सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। मौजूदा मामले में, प्रतिवादी को ऐसा अवसर दिया गया है। यह भी विवादित नहीं है कि बर्खास्तगी का आदेश पारित होने के बाद, प्रतिवादी को जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान

की गई, जिससे वह बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने में सक्षम हो गया।

इस संबंध में, यह देखा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के उक्त संशोधन के मद्देनजर, केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 15(4) में संशोधन किया गया था। संशोधित नियम 15(4) इस प्रकार प्रदान करता है:

> "15(4) - यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी आरोप की सभी या किसी भी धारा पर और जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह राय है कि नियम 11 के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट कोई भी दंड सरकारी कर्मचारी पर लगाया जाना चाहिए,और सरकारी कर्मचारी को लगाए जाने वाले प्रस्तावित जुर्माने पर अभ्यावेदन करने का कोई अवसर देना आवश्यक नहीं होगा:
>
> बशर्ते कि प्रत्येक मामले में जहां आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो,जांच का रिकॉर्ड अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आयोग को उसकी सलाह के लिए भेजा जाएगा और सरकारी नौकर पर ऐसा कोई जुर्माना लगाने का आदेश देने से पहले ऐसी सलाह पर विचार किया जाएगा।"

नियम 15(4) में उल्लिखित नियम 11 का खंड (ix) बर्खास्तगी का दंड है।

इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत या केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 15(4) के तहत सजा के खिलाफ कारण बताने के लिए दूसरे अवसर का दावा नहीं कर सकता है।

इस प्रश्न पर भारत संघ बनाम तुलसी राम पटेल, [1985] 3 एस.सी.सी. 398 मामले में इस न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी विचार किया गया था। उस मामले में, बहुमत के अनुसार यह देखा गया है कि प्रस्तावित दंड पर अभ्यावेदन करने का एकमात्र अधिकार संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) में संशोधन किए जाने से पहले पाया जाना था। संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम में ऐसा कोई कानून प्रावधान नहीं है जिसके तहत कोई सरकारी कर्मचारी इस अधिकार का दावा कर सके। इसलिए, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ दोनों को यह मानना उचित नहीं था कि बर्खास्तगी का आदेश दूषित था क्योंकि प्रतिवादी को बर्खास्तगी की सजा के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का दूसरा अवसर नहीं दिया गया था, यह थोपने से पहले।

इन परिस्थितियों में, हमने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन, जैसा कि अपील को निस्तारित करते हुये खंडपीठ ने मामले की योग्यता के आधार पर विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले पर विचार नहीं किया है, हम पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद गुणावगुण के आधार पर अपील के निस्तारण के लिए मामले को खंडपीठ को वापस भेजते हैं।

यह अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

ए.पी.जे. अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।